RCEP का अगला चरण: भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

27 जून, 2019

"भारत मुक्त व्यापार समझौता वार्ता से बाहर नहीं निकल सकता।"

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के 10-सदस्यीय संघ के नेतो 2019 के अंत तक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का निष्कर्ष निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन सब में मलेशियाई प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिससे यह संकेत मिलता है वैसे देश, जिनमें भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं, जो RCEP में अभी शामिल नहीं होना चाहते हैं, वे बाद में शामिल हो सकते हैं, जिससे 13-सदस्यीय RCEP को आगे जाने की अनुमति मिल सकती है।

अन्य का मानना है कि सभी 16 सदस्यों को अंतिम आरसीईपी दस्तावेज पर सहमत होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि आसियान, जिसने पहली बार 2012 में आरसीईपी विचार को बढ़ावा दिया था, सभी हितधारकों पर वार्ता को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन, जो रविवार को बैंकॉक में समाप्त हुआ, वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए सहमत हुआ है।

RCEP में आसियान (ASEAN) के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के साझेदार – भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं – और FTA वैश्विक जीडीपी का एक तिहाई बनाने वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच सभी वैश्विक व्यापार का 40% है। भारत इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक रहा है, लेकिन वार्ता में छह साल बाद भी इसकी चिंता बनी हुई है अर्थात् चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सस्ते सामान के लिए अपने बाजार खोलना, और यह आशा करना कि आरसीईपी देश भारतीय जनशक्ति (सेवाओं) के लिए अपने बाजार खोलेंगे, उचित नहीं है।

भारत को आरसीईपी देशों में से 11 के साथ व्यापार घाटा है और यह उनमें से एकमात्र है, जो वर्तमान में चीन के साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं कर रहा है। हालांकि, गलतफहमी के बावजूद, सरकार ने दोहराया है कि यह आरसीईपी में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत को समझौते से बाहर करने का कोई भी प्रयास बेसोचा-समझा होगा।

अगले कुछ महीनों में, भारत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वार्ता पर ध्यान दे और सबसे महत्त्वपूर्ण, आंतरिक और वैश्विक स्तर पर स्पष्ट संकेत दे कि वह आरसीईपी में शामिल हो रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने ऐसे उद्योगों के हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है, जो स्टील और एल्युमिनियम, तांबा, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स सहित आरसीईपी के बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं तथा क्षेत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में एक आम सहमति विकसित करने के लिए थिंक टैंक और प्रबंधन संस्थानों को शामिल किया है।

आरसीईपी में शामिल होने का मौका गंवाने का मतलब यह होगा कि भारत न केवल क्षेत्रीय व्यापार से चूक जाएगा, बल्कि नियमों को फ्रेम करने की क्षमता और समूह के लिए निवेश मानकों को भी खो देगा। वैश्विक अनिश्चितताओं और बहुपक्षवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समय, RCEP पर एक नकारात्मक संदेश आर्थिक विकास के लिए भारत की योजनाओं को कमजोर करेगा।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय एवं चीनी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु एक-दूसरे के बाजार तक पहुँच पर आम सहमति बनाना था।

उद्देश्य

- 16 सदस्य देशों के इस समझौते को लेकर आगे की बातचीत के लिए राजनीतिक मार्गदर्शन की जरूरत है।
- वस्तु, सेवा, निवेश, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल करना।

क्या है?

- यह दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के दस सदस्यीय देशों तथा छः अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड), जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है।
- प्रभाव में आने के पश्चात् यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा, जिसमें विश्व की 45 प्रतिशत आबादी शामिल होगी व इसकी संयुक्त GDP लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर होगी।
- साथ ही यह विश्व व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत भाग को कवर करेगा।
- आर.सी.ई.पी. वार्ता की औपचारिक शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हो गई थी।
- आर.सी.ई.पी. को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- आर.सी.ई.पी. के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर और इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 39 प्रतिशत है।
- इससे पहले बैंकॉक में 23वें दौर की बातचीत हाल में संपन्न हुई, लेकिन उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई।

सदस्य देश

- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- इनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी देश हैं।

क्या है आसियान?

- आसियान दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। 10 दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर बनाया गया है।
- इस संगठन का उद्देश्य सभी 10 देशों के बीच आर्थिक साझेदारी, व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करना है।
- इस संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

Committe

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. यह आसियान तथा 6 अन्य देशों का मुक्त व्यापार समझौता है।
   2. यह प्रभाव में आने के बाद विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा।
   3. भारत का RCEP देशों में से 11 के साथ व्यापारिक घाटा चल रहा है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3

   (c) केवल 1 (d) 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).**

   1. It is the Free Trade Agreement of ASEAN and 6 other countries.
   2. It will be the world's largest free trade agreement after coming into effect.
   3. India has trade deficit with as many as 11 of the RCEP countries.

   Which of the above is / is the statement true?

   (a) 1, 2 and 3 (b) 1 and 3

   (c) Only 1 (d) 2 and 3

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) क्या है? इसके सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, भारत के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? परीक्षण कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. What is Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? How can the free trade agreement with its member countries be useful to India? Examine.

(250Words)

नोट : 26 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

Committed To